समय पर अदायगी किए जाने, और यह भी विद्युत गृहों पर उचित रूप में उतराई किए जाने संबंधी व्यवस्था किए जाने संबंधी अवरोधों के अधीन है। वास्तव में, विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति तथा संचलन किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें गुजरात में स्थित विद्युत गृह भी शामिल हैं।

Allocations made for poverty alleviation programmes

*13. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the allocations made to different State during the current financial year for implementing IRDP, JRY, PMRY and other poverty alleviation programmes;

(b) the target fixed for implementing these programmes during the current financial year;

(c) the State-wise expenditure percentage and achievement as on 31st October, 1995; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA) : (a) to (d) Three major Centrally Sponsored Poverty Alleviation Programmes which are being implemented to in the rural areas of the country are: (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP); (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY); and (iii) the Employment Assurance Scheme (EAS). Information available on financial and physical performance under three programmes during the current year is given at Annexure [*See* Appendix 175 Annexure No. 5]

The Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) provides self employment to educated unemployed youth both in rural and urban areas. The scheme has been designed to provide employment by setting up of micro enterprises by the educated unemployed youth. It relates to the setting up of self employment ventures through industry, service and business routes. Self Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY) which was in operation from 1983-84 to 1993-94 has been subsumed in the PMRY. Information available on State-wise progress under PMRY (1995-96) upto October, 1995 is given at Annexure [*See* Appendix 175 Annexure No. 6]

सब्जियों की बिक्री संबंधी समाचार

*14. श्री राम देव भण्डारी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 1995 के "हिंदुस्तान" के दिल्ली संस्करण में "अब सब्जी को रंग कर बेचा जा रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में कुछ सब्जी की दुकानों पर छापे मारे हैं। उन्होंने पाया कि कुछ सब्जी विक्रेता कुछ सब्जियों को रंग रहे हैं ताकि वे ताजा दिखाई दें।

इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सब्जी की दुकानों के निरीक्षण कार्य को तेज किया है। जुलाई, 1995 में तीन नमूनों को अपमिश्रित पाया गया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। विभाग ऐसे विक्रेताओं पर निरन्तर निगरानी रख रहा है।

देश में निर्यात आयात जोन

*15. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्यात-आयात जोनों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश से निर्यात किए जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और देश के कुल निर्यात में इसके योगदान की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में निर्यात की विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस राज्य में निर्यात जोन की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) देश में सात निर्यात संसाधन जोन (ई०पी०जैड) कार्यरत हैं जो बम्बई (महाराष्ट्र), काण्डला (गुजरात), नौएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

(ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) एक निर्यात संसाधन जोन नौएडा, उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। मौजूदा निर्यात संसाधन जोनों में उपलब्ध निधि और मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं को इष्टतम बनाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार के पास फिलहाल देश में किसी नए जोन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अब राज्य सरकारों अथवा संयुक्त/निजी क्षेत्रों द्वारा भी भारत सरकार का अनुमोदन लेने के पश्चात नए निर्यात संसाधन जोनों की स्थापना की जा सकती है।

Increase in Prices of edible oils

*16. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the increase in prices of edible oils, during the last six months;

(b) the gap between demand and supply of edible oils in the country; and

(c) how the Government propose to fill this gap?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH) : (a) The percentage variation in the Wholesale Price Indices of edible oils during the last six months has been as under:

Oil	Percentage variation in prices
Groundnut	+2.3
Mustard	+6.0
Vanaspati	−4.3
Cottonseed	−0.2
Edible Oils (sub-group)	+1.8

(b) The gap between demand and supply of edible oils in the country in the year 1995-96 is estimated to be of the order of 7-8 lakh M.Ts.

(c) Some of the steps taken by the Government to fill the gap are:—

(i) Import of all edible vegetable oils except coconut oil, palm kernel oil, RBD palm oil and RBD palm stearin has been placed under OGL w.e.f. 1.3.95.

(ii) Customs duty on import of edible oils under OGL has been reduced to 30%.

(iii) STC has been authorised to import 1.5 lakh MT of RBD palmolein for PDS at 20% customs duty.

(iv) NDDB has also been allowed to import 1.5 lakh MT of edible oils at the concessional duty of 20%.

In addition, Govt. has also taken a number of measures to augment the production of oils from indigenous sources like intensification of efforts for implementation of Oilseed Production Programme by the Ministry of Agriculture, better incentive to producers through fixation of minimum support prices of oilseeds and providing fiscal incentives for increased exploitation of oils from non-conventional sources.